



ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। उन्होंने देशनोक के पलाना गांव की रोही में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया।

अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की होगी

बीकानेर, 22 मई (कास)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी. दूर देशनोक के पलाना गांव की रोही में हुई विशाल जनसभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारी जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दो दृक संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगांम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से और देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे

■ जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में पहचान बनायेगी।

■ पलाना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले बालाकोट के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली सभा यहाँ हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ऐसा संयोग बना है।

हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है और अब तो मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा, न ही बातचीत होगी। यदि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को

वापस लेने की। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमापार पाकिस्तान का रहीमयार

खान एयरबेस अगले कई दिनों के लिए बंद हो चुका है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस-नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान की रीफाइनी का काम भी अंतिम चरण में है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्वभर में अपनी पहचान और बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रम्प के मध्यस्थता के दावे को केवल कल्पना बताया

ट्रम्प की नाराज़गी सहने के लिये भारत को तैयार रहना पड़ेगा

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। "अमेरिका केवल अमेरिका तक ही सीमित था।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

10 मई को युद्धविराम घोषित होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव देकर यह शांति स्थापित करवाई थी।

जो कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच की संवेदनशीलता और विवाद की पुष्टभूमि से जरा भी परिचित है, वह जानता है कि ट्रंप का यह दावा कितना अतार्किक और हास्यास्पद है। यही कारण है कि भारत, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्धविराम केवल दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के डील मेकर का क्रेडिट लेने की कोशिश को खारिज करने के निस्संदेह अलग नतीजे होंगे। इससे

■ ट्रम्प के दंभ भरे दावों को अब विश्व ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, चाहे एक ही दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की घोषणा हो, या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी हो, या यमन के हूती को अपनी भारी नौ सेना से डराने का प्रयास हो, या ईरान के अयतुल्ला खमेनी को चेतावनी देने की कोशिश हो।

■ अतः बार-बार भारत-पाक के बीच अपनी मध्यस्थता से सीज़फायर कराने का दावा, ट्रम्प की मजबूरी बन गया है।

■ पर, भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्रम्प को इस "सीज़फायर" के लिए कोई भी श्रेय नहीं देना, ट्रम्प प्रशासन के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस खीज की गाज, भारत पर गिर सकती है।

पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि यदि वे चुने जाते हैं तो यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं-जो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना साबित हुई। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल रहने के बावजूद, ट्रंप लगातार खुद को रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया का नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ट्रंप को ज्यादा तवज्जो नहीं देते।

ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने की बार-बार की धमकियों के बावजूद, पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर दिया, यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बनाया, ठीक उसी समय, जब अमेरिका खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा था।

इस सबके बीच, ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता तब सामने आई, जब उन्होंने

दावा किया कि यूक्रेन युद्ध केवल तब खत्म होगा, जब वे स्वयं पुतिन से बात करेंगे। उनके कैबिनेट सदस्य बार-बार उनकी "शानदार शक्तियत" की तारीफ करते रहे, उनका मत था कि ट्रंप का करिश्माई व्यक्तित्व पुतिन को शांति की ओर ले जाएगा।

हालांकि, पुतिन से दो घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद भी शांति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी। उल्टा, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे यूक्रेनी जनता को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप की इन लगातार कूटनीतिक विफलताओं के बीच, अमेरिका इतना व्यग्र है कि "सफलता" के मामूली से संकेत तक को लपक लेना चाहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नौसेना पर हमला किया, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठा को गहरा अघात पहुंचा। इसके बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका और ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 22 मई। महिला उल्पीडन मामलों की विशेष अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाह के तीन माह बाद ही विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में उसके पति विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन

■ मृतका के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने बताया था कि उसका पति व ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते हैं।

अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुंदर भविष्य का सपना देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है। उस समय लड़की के मन में यह विश्वास होता है कि उसका पति, उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने

सतपाल मलिक, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर थे तथा उस दौरान उन पर किरू में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का ठेका देने का आरोप लगाया गया था

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 मई। प्रतिशोध का मामला प्रतीत होने वाली एक कार्यवाही के अन्तर्गत, सी बी आई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह प्रकरण कोरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रु. के 'सिविल वर्क्स' का ठेका दिये जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अधिकारियों ने आज कहा कि एंजेंसी ने 3 साल की जांच पड़ताल के बाद, अपने निष्कर्ष एक विशेष अदालत में पेश कर दिये हैं। इस प्रकरण मलिक एवं पांच अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं।

आज 'एक्स' पर डाली गई पोस्ट में मलिक ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं।

पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उनके

■ सीबीआई ने इस आरोप की तीन साल तफतीश करके यह चार्जशीट दाखिल की है।

■ सतपाल मलिक ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि वे किसान पुत्र हैं तथा सरकार उन्हें डराना व दबाना चाहती है, पर, वे झुकेंगे नहीं।

■ सतपाल मलिक ने एक्स पर यह भी कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा अस्वस्थ हैं। अतः उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, जो उन्हें फोन कर रहे हैं।

पास बहुत से शुभचिन्तकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर पा रहे हैं। सी बी आई गत वर्ष फरवरी में इस केस के मामले में मलिक एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी।

सी बी आई ने 2022 में एफ आई आर दर्ज करने के बाद, एक बयान में कहा था कि यह केस 2019 में कोरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर (एच ई पी) प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का 2200

करोड़ रु. का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिये जाने में की गई कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

मलिक, जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों पर स्वीकृति देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर, 22 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की

■ अदालत ने पुरुषोत्तम दाधीच की पेपर लीक मामले में दायर अपराधिक याचिका खारिज की।

एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में संरेख करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, 22 मई। पाँको मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने

■ अभियुक्त ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबर्न दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 32 प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी हमलों में भूमिका को समझाने, विश्व यात्रा पर निकले

ये प्रतिनिधिमंडल लगभग तीन दर्जन देशों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान की भूमिका के प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे

दुर्लभ एकता के इस प्रदर्शन के बावजूद भी इस पहल ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के चयन में संबंधित दलों से औपचारिक सलाह-मशविरा नहीं किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को कथित तौर पर पार्टी की औपचारिक सहमति के बिना शामिल किया गया, क्रिकेटर से राजनेता बने तुषमूल सांसद युसुफ पठान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसने दलों के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई, जो प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा

■ पर, एक प्रकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मोदी सरकार की सराहनीय सफलता का मुँह में पूरा स्वाद आता उससे पहले कुछ किरकिरी आ गई, विपक्ष की कुछ पार्टियों की इस शिकायत से कि उनसे पूछा नहीं गया, उनके नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने से पहले।

■ इस आंतरिक विवाद का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में "महायुति" गठबंधन में भी उथल-पुथल हो सकती है। शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार के दोनों धड़े अब एक होने के प्रयास में लगभग सफल हो गये हैं तथा देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार को इससे मजबूती मिलेगी।

■ प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस नीति से घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो गई है, जिसका असर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी समय तक प्रभावी रहेगा।

प्रचारक से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा पर लंबे समय से नजर रखते आए हैं, ने इस कदम की

आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए,

प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति पार्टियों के भीतर आपसी कलह को जन्म दे रही है। एकता के नाम पर इस तरह का

विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। –इटैलियन कहावत

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न राय के लिये भेजे हैं, जनता उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट की राय जानने को

मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल, 2025 में जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल शीर्षक के केस में दिया था, जिसमें यह माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अपने पास अनिर्णित रखने का अधिकार एक सीमा तक होना चाहिये और न्यायालय ने तीन माह की सीमा निर्धारित की। इस निर्णय की वैधता पर उपराष्ट्रपति धनखड ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि 'हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा।' अब राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न भेजे हैं और कोर्ट की सलाह मांगी है। इनमें एक प्रश्न उपरोक्त विषय के बाबत भी है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जानना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत 3 महीने की समय अवधि तय कर सकते हैं, जबकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीया राष्ट्रपति ने उक्त फैसले को संवैधानिक मूल्यों, संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं के विरुद्ध माना है, इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी माना है।

इस पर विचार करने के हेतु हमें संविधान व अनुच्छेद 143 को समझना होगा, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 200 व 201 की व्याख्या करनी होगी। समय सीमा नहीं है, फिर भी क्या राज्यपालों व राष्ट्रपति के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वे अपने पूर्ववर्ती फैसल पर पुनः विचार कर निर्णय दे सकते हैं, वह भी अनुच्छेद 143 के आधार पर।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 निम्नलिखित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है:–

1. अनुच्छेद 200के तहतू राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह और मदद के लिए बाध्य है?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की पूरी तरह रोक सकता है?
5. संविधान में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
7. क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है।?
8. क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?
9. क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है?
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है।
11. क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सबीकृत के बिना लागू किया जा सकता है?
12. क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों को भेजना अनिवार्य है?
13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है, जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो?
14. क्या केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

हमारा संविधान कई विशिष्टताओं से भरा हुआ है। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने 'हमारा संविधान' नामक पुस्तक में जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वे अद्भुत हैं और निम्नलिखित हैं:–

“भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। वह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास सांचे–ढाँचे में या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनन्य तथा नन्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का मिश्रण है इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तिवों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्तों के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान में अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जीवित रहा। यह बात स्वयंमेव उसकी सुस्पष्टता, सक्रियता और सर्ववृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।”

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। जहां कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। संसद कतिपय प्रतिबन्धों के रहते हुये संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं जो दर्शाता है कि संविधान विकास की गति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उद्घोषणा की है कि लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ अर्थात् न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सब समान हैं, अपने कार्य में, अपने–2 अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं।

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है यदि उसके विषय में उसका विचार हो कि ऐसी राय मानना समीचीन है। यह राय केवल सलाह के रूप में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिये अपनी राय देना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Special Reference No.1/1964 में यह मत अभिव्यक्त किया है। Re the Special Courts Bill, 1978 में कोर्ट ने ईंगित किया है कि यदि कोई इन्कार करे तो उसके कारण केस आयर्यक है। अयोध्या बाबरी मस्जिद के केस रैफरेस संख्या 1/1993 को न्यायालय ने रेफरेन्स को बिना उत्तर दिये लौटा दिया था। अहमदाबाद सेन्टजेवियर कॉलेज सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के केस में (1974)एससीसी 717) माना है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई ऑपिनियन बाध्यकारी नहीं है। हाँ, यह वजन रखती है; किन्तु यह भी सच है कि जस्टिस बाबू जी चन्द्रचूड ने यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह सभी कोर्ट्स के लिये बाध्यकारी होना चाहिये।

कावेरी विवाद के मामले में (Special Reference No. 1 of 1998) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेफरेन्स की शक्ति को अपीलव्य शक्ति नहीं माना जा सकता। कावेरी रेफरेन्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राष्ट्रपति पूर्ववर्ती निर्णित किये हुये मामले में रेफरेन्स नहीं कर सकते। क्योंकि जब निर्णय दिया है तो फिर शक की कोई संभावना नहीं रहती। 2ब् रेफरेन्स ऑफ 2012 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी विषय पर कोई निर्णय है तो पुनः कोई कार्यवाही नहीं हो सकती (Central for Public Interest Litigatin vs UOI, 2012)

उपरोक्त कुछ मामले, जिनका उल्लेख किया है विषय को समझने व निर्णित करने में सहायक हो सकते हैं। अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी बात पूरे देश के (सभी न्यायालयों पर लागू है)। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायलय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। किन्तु यह भी सच है कि क्या कोई बात कहने मात्र से, उसे कानून माना जा सकता है। इसका उत्तर 'ना' में दिया है, क्योंकि तर्क के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कानून घोषित हुआ है।

संसद जब विधेयक (एक्ट) बनाती है तो उसमें प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति की एसेन्ट प्राप्त करे और यह घोषित करे कि वह जनता पर कब लागू होगा। विधेयक (अधिनियम), गजट विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित तारीख से लागू होता है। ऐसा भी देखा गया है कि संसद ने कानून तो पारित कर दिया, किन्तु लागू करने की विज्ञप्ति ही जारी नहीं की। Industrial Disputes Act 1947 में एक संशोधन 1982 में हुआ, जिससे Industry की परिभाषा में परिवर्तन किया गया; किन्तु संशोधन एक्ट के लागू होने की तारीख आज तक घोषित नहीं की। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां सरकार कानून बना देती है, किन्तु वह लागू नहीं करती। कानून लागू करने के हेतु हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया को एक्जीक्यूटिव आदेश न मानकर विधायिकी प्रक्रिया माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के प्रकरण में राज्यपाल को विधेयकों को लम्बित रखने को असंवैधानिक करार दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल, तेलंगाना व पंजाब राज्यों में वहां के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लम्बित रखने से राज्य सरकार के कामों में बाधा पैदा हो रही है।

किसी विधेयक को लम्बित रखने की सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सरकार ने चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने अनुव्देद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है।

चुनौती देने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है तथा यह भी बहस का ज़ा रही है कि लोकतांत्रिक सरकारों पर किसी प्रकार का बन्धन जर्नाहित के विरुद्ध है, क्योंकि सरकार जनता की सरकार है।

राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाकर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राय मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिये किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये समय सीमा तय कर सकता जबकि संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं है? (पूछे गये 14 प्रश्नों का यह सार है)। एक दृष्टिकोण ऊपर अभिव्यक्त किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम अनेकान्त भाव से विचार करें तो यह हो सकता है कि अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने के हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा किया जा सकता है, यदि उक्त अनुच्छेद की परिस्थितियां विद्यमान हों। सके अतिरिक्त अनुच्छेद 141 भी यह निर्देश देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी घोषणा कानून है।

अब उपरोक्त 14 प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कानून स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिये बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार का अधिकार है। मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



सुनील दत्त गोयल

कश्मीर घाटी की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रश्न केवल सुरक्षा या आर्थिक विकास का नहीं है – बल्कि वहां की जनसांख्यिकीय संरचना (अर्द्धज्म एंस्ले) का है। जब तक घाटी में जनसंख्या का सामंजस्य नहीं स्थापित किया जाता, तब तक किसी भी योजना या नीति की सफलता अधूरी ही मानी जाएगी। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक था।

मस्जिदों से खुलेआम धमकियाँ दी गईं, गैर मुस्लिम लोगों के घरों पर हमले हुए, बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनका सरेंआम कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया,

लूटपाट की गईं, उनको जमीन जायदाद और अपने घरों से बेदखल किया गया और इतना वीभत्स नरसंहार हुआ कि आज उसकी कल्पना मात्र से भी दिल कांप उठता है और पूरा का पूरा समुदाय अपनी ही ज़मीन से दर-ब-दर कर दिया गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगे उन अस्थायी कैपों से लेकर आज भी विस्थापन का दर्द झेलते परिवारों तक – यह घाव आज भी हरा है। द कश्मीर फाइल पिक्चर में इसके अंश लोगों ने देखे हैं और वह उससे कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में जो अंश दिखाए गए उससे कई गुना अधिक उनकी भयानकता थी।

घाटी में पहले कश्मीरी पंडितों, सिखों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति और उनका बौद्धिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक योगदान रहा है। लेकिन कट्टरपंथी सोच और अलगाववादी मानसिकता ने वहां एकपक्षीय धार्मिक पहचान को जबरन स्थापित करने की कोशिश की – और काफी हद तक सफल भी हुए।

जनसंख्या का संतुलन क्यों जरूरी है?

कश्मीर घाटी की एकांगी

जनसंख्या संरचना केवल सामाजिक

असंतुलन का कारण नहीं है, बल्कि यह

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी दीर्घकालिक

खतरा है। जब घाटी में स्थानीय समर्थन

के बल पर विदेशी आतंकवादी शरण पाते हैं, जब ओवर टाउंड वर्कर आतंकियों को आश्रय एवं सूचनाएं भी देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल सीमा पार से नहीं, भीतर से भी है। कश्मीर में एक वार् एसा है जो आतंकवादियों का खुला समर्थन करता है, और दूसरा वर्ग है जो व्यापार के लिए मीठी-मीठी बातें करता है, शांति के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर जुलूस निकालता है। लेकिन यह उनकी दोहरी नीति है – आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो स्थानीय व्यापारी सच में शांति और ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसे यह बताना होगा कि कौन लोग आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। अगर वह सच में ईमानदार है, तो उन्हें अपने आसपास की सच्चाई सरकार को बतानी होगी। एक ओर मोमबत्तियां जलाकर शांति की बातें होती हैं, तो दूसरी ओर उसी मोहल्ले से आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में अगर कोई यह कहे कि घाटी में आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ चल सकते हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक भ्रम होगा।

समाधान क्या है?

जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक मात्र

विकल्प नहीं है, लेकिन यह सबसे

निर्णायक विकल्प जरूर है।

सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के युवाओं, अगिन वीरों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों, ऐसे लोगों और व्यापारियों को जो अपने व्यापार का विस्तार कश्मीर में करना चाहते हैं तथा राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत नागरिकों को घाटी में पुनर्वासित करने की योजना तैयार करें। उन्हें:–

भूमि, आवास और रोजगार व बैंकों से सुविधाजनक कर्ज की सुविधाएं दी जाएं,

वहां सम्मानजनक जीवन यापन की गारंटी हो,

और एक वर्ष की अनिवार्य सैन्य

प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा में भी

सहभागी बनाया जाए।

यह रणनीति घाटी में स्थायी शांति

और विकास के लिए आधार तैयार

करेगी।

क्या यह व्यावहारिक है?

बिल्कुल। धारा 370 के हटने के

बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार

भारतीय कानून और नीतियों को समान

रूप से लागू करने का अवसर मिला है।

निवेश बढ़ रहा है, नौकरियां पैदा हो रही

हैं – लेकिन अगर इस बदलाव का लाभ

केवल एक सीमित समुदाय तक ही रहे,

तो ना तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के

हित में होगा और ना ही वहां के व्यापार

और उद्योग जगत के सर्वांगीण विकास

के लिए उचित होगा। क्योंकि सरकार जितना बड़ा विकास कश्मीर घाटी के लिए करना चाहती है उसके लिए उतने ही संसाधनों की और मानव श्रम की और मानवीय लोगों की जरूरत रहेगी और उसके लिए बाहर के राज्यों के लोगों को वहां विस्थापित करना आवश्यक है जो कि वहां के स्थानीय लोगों के हित में भी रहेगा और व्यापार उद्योग जगत के लोगों के भी हित में रहेगा। कश्मीर की वास्तविक ‘विकास गाथा’ तब लिखी जाएगी, जब वहां का जनसंख्यिकीय संतुलन भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुलतावादी और समावेशी होगा। यह न केवल विस्थापितों के साथ ऐतिहासिक न्याय होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और समरस भारत की नींव भी होगी। सरकार को अब संकोच नहीं, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता दिखाने की जरूरत है। कश्मीर में अगर स्थायी समाधान चाहिए, तो डेमोग्राफिक चेंज ही वो निर्णायक चाबी है, जो दरवाजा खोल सकती है – शांति और समरसता का।

धन्यवाद,

–सुनील दत्त गोयल,

महानिदेशक, इम्पीरियल

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टािक

एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर,

राजस्थान

रोजगार के बेहतर विकल्प माध्यमिक शिक्षा के साथ हो



राजेन्द्र जोशी

शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है। अंकों का जोड़-तोड़ शिक्षार्थी को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। शिक्षा के जरिए स्कूलों में काम का वातावरण और संस्कृतियों में परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा , शिक्षकों के साथ उनकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा। तभी वह अपना प्रभाव ढंग से काम करते हुए शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों को काकर्षक कर सकेंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उच्चशिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मध्य में उपयोगी वोकेशनल कोर्स संचालित किये जाए ,जिससे छात्रों को काम करने में सक्षम बनाया जा सके। जरूरत प्रैक्टिकल स्किल और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की है, बच्चों का मन व्यावसायिक शिक्षा की तरफ एकदम से नहीं जा

सकता। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का कोई पारिवारिक परिवेश व्यवसायिक नहीं होता। एक बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित करने से पहले ऐसे शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो व्यवसायिक शिक्षा के लिए खुद पूरी तरह प्रशिक्षित हों। अनेक बार हम यह मान लेते हैं कि शिक्षक हर कार्य में परागत होगा। शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन करियर प्रबंधन में उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत सदैव बना रहनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान

शिक्षार्थी को विद्यार्थी परामर्श केंद्र के

माध्यम से उसकी इच्छा और रुचि

टटोलनी होगी। शिक्षार्थी माध्यमिक

शिक्षा तक यह समझ ही नहीं पाता कि

उसे अब किस ओर अपना कैरियर

बनाना है। यह सही और जरूरी वक्त

होता है जब शिक्षार्थी को उचित सलाह

और परामर्श मिले। यह परामर्श

माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद नहीं

अपितु माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही

वह अपना मानस और मस्तिष्क यह

तय कर ले कि माध्यमिक शिक्षा के

उपरांत उसे क्या काम करना है, नौकरी

करनी है तो किस सेक्टर में करनी है,

व्यवसाय करना है तो किस सेक्टर में

करना है। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम

से उसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो

कैसे जाना है, उसकी रुचि के अनुसार

उसका मस्तिष्क एकाग्र हो जाना

चाहिए। वर्तमान समय में बाजार में

विकल्प बहुत है, लेकिन उचित

मार्गदर्शन और चयन की समस्या बनी

हुई है, अगर समय रहते शिक्षार्थी को उचित मार्गदर्शन मिले और उसके साथ ही उसे जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त हो तो विकल्प तराशने में आसानी हो सकती है।जिससे वह अपना आगे का कैरियर चुन सके। बेहतर विकल्प चुनने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित कैरियर सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों को उनके भविष्य के बारे में सही दिशा दिखा सकें। कैरियर सलाहकार पूरे समय विद्यालय के दौरान छात्रों से परिचित रहे, और उनकी रुचि, क्षमता और लक्ष्य को समझे। उनकी क्षमताओं को समझकर सही कोर्स, व्यवसाय और नौकरी के विकल्प बता सकें।

व्यवसायिक शिक्षा के कोर्स

माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ

संचालित किये जा सकते हैं। शिक्षार्थी

को माध्यमिक शिक्षा के बाद कहीं और

भटकना न पड़े और अपने विद्यालय

के माध्यम से वह अपने वोकेशनल

सिखने चुनते बेहतर विकल्प तलाश

कर ले। वैसे भी देश में युवाओं की

बढ़ती बेरोजगारी हमारी सरकारों और

समाज की चिंता बनी हुई है। इस गंभीर

समस्या से निपटने के लिए माध्यमिक

शिक्षा स्तर पर विकल्प तलाश करना

ही उचित होगा।

देशभर में बढ़ती बेरोजगारी से

निजात पाने के लिए इस चुनौती को

स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति के

अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में

व्यवसायिक विषय को पढ़ाने के लिए

पर्याप्त संख्या में परामर्शक, प्रशिक्षित

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इसके लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला एवं अन्य उपकरण जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जरूरी नहीं है कि परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक– सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर स्कूलो का एक समूह गठन कर पांच–दस किलोमीटर के दायरे में अपने वहां सभी स्कूलों में ऐसे लोग समय निर्धारित कर विद्यार्थियों को परामर्श दे सकते हैं। चुनौती यह है कि बेरोजगारी की समस्या पर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही मूल्यंकन और आंकलन किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे देश के विद्यार्थी रोजगार, व्यवसायिक कि तरफ अपने बेहतर विकल्पों का चयन कर लें।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थानों से परिचित होना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाना चाहिये हो सके तो विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थाओं की विजिट भी करवाई जा सकती है। कोर्सज तलाशने और प्रशिक्षण रुचि अनुसार 12 वीं कक्षा से पूर्व और 12 वीं कक्षा के दौरान दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। देश भर में रोजगार के अनेक विकल्प है उसमें से बेहतर विकल्प वर्ष में विद्यार्थी को चुनने का अवसर मिलेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। विचार तो इस पर भी

होना चाहिए की 12 वीं कक्षा के बाद एक वर्ष और उसी विद्यालय में कोर्सज संचालित किया जाए। जिससे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षार्थी को कहीं और न जाना पड़े। वहीं वोकेशनल कोर्स करने की व्यवस्था हो सके इस विषय पर शिक्षा प्रशासन और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक स्कूलों परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल राजकीय स्कूलों तक सीमित ना हो बल्कि पब्लिक स्कूल, निजी स्कूलों और सार्वजनिक स्कूलों में भी इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। हां यह जरूर है कि अगर उनके पास इसकी उचित व्यवस्था प्रारंभ में ना हो तो राजकीय परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक निजी और सार्वजनिक स्कूलों की मांग पर उनको सेवाएं उपलब्ध करा सके। व्यवसायिक शिक्षा एक साथ संचालित हो तभी बेहतर विकल्प शिक्षार्थी के पास उपलब्ध हो सकेंगे। देश की बेहतरी के लिए व्यवसायिक शिक्षा ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था व्यवसायिक शिक्षा के साथ भविष्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। तभी हम अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान तलाशने में कामयाब हो सकेंगे।

–राजेन्द्र जोशी,

शिक्षाविद-साहित्यकार

जैव विविधता दिवस पर प्रतियोगितायें आयोजित

भीलवाड़ा, (निर्स)। भारतीय सांस्कृतिक निधि इन्टेक चेंटर भीलवाड़ा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर म.ग.ा. राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को मुख्य वक्ता के रूप

में संबोधित करते हुए इ

सार-समाचार

पुलिस ने चैंकिंग अभियान चलाया

जोधपुर, (कासं)।पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के आदेशा एवं निर्देशानुसार पुलिस ने बुधवार की शाम और रात में अलग अलग समय में चैंकिंग अभियान चलाया।पुलिस ने इस दौरान ३२४ संदिग्ध वाहन चैक के साथ राजकोप ऐप पर १५० संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान किया। बुधवार की शाम सात से रात ११ बजे तक , रात्रि कालीन गश्त वक्त १२ बजे से सुबह ०५ बजे तक के दौरान संदिग्ध वाहनों की चैंकिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों, टैक्सी चालकों के विरुद्ध, खतरनाक तरीके, तेज गति से चलाने वाले, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट की कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया। जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में कुल ३२४ संदिग्ध वाहन चैक किए गए तथा राजकोप ऐप पर १५० संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ २९ संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा भी भरा गया तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों ६० पुलिस एक्ट में १५ कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने वाले १९ वाहन चालकों का १८५ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा १३ बंपर लगे वाहनों, ०७ बिना नंबरी वाहनों, ११ काला शीशा लगे वाहनों, १२ टैक्सी चालकों तथा ०१ खतरनाक तरीके से चलाने वाले वाहन चालक, ०३ रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत चालान बनाए गए।

वैन पलटने से ५ जने घायल

पाली, (नि.सं.)। पाली में गुरुवार की सुबह एक वैन असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में वैन में सवार ५ जने घायल हो गया और २ जनों को चोट आई। सभी पांच घायलों को उपचार के लिए पाली के बांगड हॉस्पिटल लाया गया। जहां ट्रॉमा वार्ड में उनका उपचार जारी है। हादसे में घायल बूंदी जिले के सिसौला गांव निवासी २० साल की पूजा पुत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि वे बुधवार सुबह ओम बन्ना दर्शन के लिए परिवार के ७ जने रवाना हुए थे। गुरुवार सुबह ओम बन्ना मंदिर से कुछ पहले गाड़ी असंतुलित हो गई और सड़क किनारे उतर कर पलट गई। बूंदी जिले के सिसौला गांव निवासी २० साल की पूजा पुत्री गजेंद्र सिंह, ४५ साल के गजेंद्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, ३५ साल की खुशबू पत्नी बृजेश सिंह, ३० साल के कल्याणसिंह पुत्र बृजराज सिंह और १८ साल की टीना पुत्री थानसिंह घायल हो गए। जिनका बांगड हॉस्पिटल में उपचार जारी है। दो जने चोटिल हो गए।

यात्रियों के लिए टीन शेड की मांग

जालोर, (नि.सं.)। ऑटो रिक्शा मजदूर संघ जालोर के जिलाध्यक्ष अंबालाल माली ने अस्पताल चौराहे पर यात्रियों के बैठने के लिए टीन शेड लगाने की मांग को लेकर जालौर जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मे बताया कि जालोर के अस्पताल चौराहे पर रोडवेज की बुकिंग खिडकी जालोर से जोधपुर जाने वाली बसों की भी लगी हुई है। वह जालोर से भीनमाल जाने वाली बसो की भी बुकिंग खिडकी लगी हुई है, लेकिन रोडवेज बसों के यात्रियों के बैठने के लिए व सिर ढकने के लिए भी छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था अस्पताल चौराहे बुकिंग पर नहीं है। रोडवेज बसों की यात्री जब तक बसें नहीं आती है तब तक बसों का इंतजार कड़ी धूप में खडे रहकर करना पड़ता है। वैसे भी जालौर में पहाड की वजह से तापमान ज्यादा रहता है ऐसी भीषण गर्मी में नगर परिषद द्वारा टीन शेड दोनों बुकिंग खिडकी पर लगाया जाए तो यात्रीगण छाया में आराम से बैठ सके। पहले भी नगर परिषद द्वारा रोडवेज की दोनों बुकिंग खिडकी पर टीन शेड लगाए हुए थे। कलेक्टर से आग्रह है कि नगर परिषद को पाबंद कर टीन शेड लगाने की मांग की।

गुड़ामालानी में तिरंगा यात्रा का स्वागत

गुड़ामालानी, (कासं)। सेना के सम्मान में पंचायत समिति पायला कला चौपल माता मन्दिर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ । तिरंगा यात्रा को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई एवं सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की तीनों सेनाओं के साहस से पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली । तिरंगा यात्रा पायला कला से गुडामालानी पहुंची । जहां गांव के ग्रामीणों ने जगह-जगह फुलों कि बरसात कर स्वागत किया । वहीं व्यापार मंडल के द्वारा यात्रा में चल रहे लोगों के लिए स्टाल लगाकर शीतल पेय जल की व्यवस्था भी की गई। यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लेने के साथ वाहनों को काफिला साथ रहा । भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत के जयकारों से कस्बा गुंज उठा। तिरंगा यात्रा पायला कला से गुडामालानी होती हुई राम जो गोल , धीरीमन्ना पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा में विधानसभा क्षेत्र गुडामालानी के हजारों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

वाटर कूलर पर करंट से एक की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के बोरानाडा रीको एरिया में एक हैण्ड्रीक्राफ्ट फैक्ट्री में वाटर कूलर पर पानी पीते समय एक व्यक्ति को करंट लग गया। गंभीर रूप से झुलसने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मृतक के पुत्र की तरफ से मर्ग दर्ज किया है। बोरानाडा पुलिस ने बताया कि भोपालाढ के देवीनगर बेरा के पास रहने वाले राजेश माली की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके पिता हनुमानराम माली को बोरानाडा रिको एरिया में एक हैण्ड्रीक्राफ्ट फैक्ट्री में कूलर पर पानी पीते समय वाटर कूलर से करंट लग गया। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मगर बाद में उनकी मौत हो गई। बोरानाडा पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया।

केन्द्रीय कारागृह का निरीक्षण

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान माह मई के अनुसार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला) पूरण कुमार शर्मा, एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला डॉ. मनीष हरजाई, द्वारा गुरुवार को केन्द्रीय कारागृह का मासिक निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा जेल में बंदियों के लिए बनाए जाने वाले खाने की गुणवत्ता, रसोई घर, जेल अस्पताल, साफ-सफाई एवं जेल विधिक सहायता क्लिनिक इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा जेल अस्पताल में स्टॉफ की कमी को सुधारने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह श्री प्रदीप लखावत, जेलर हनवंत सिंह, चीफ एलएंडीसी प्रमेन्द्र पुरी एवं निजी सहायक आनंद जोशी उपस्थित रहे।

बंद मकान में चोरों ने लगाई सैध

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती बनाड़ स्थित नांदड़ी बालाजी नगर में एक बंद मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोर घर से नगदी जेवरत चोरी कर ले गए। इस बारे में मकान मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बनाड़ पुलिस ने बताया कि नांदड़ी बालाजी नगर निवासी अनिल पुत्र जगदीश वाल्मिकी की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि कल शाम को उसके मकान से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ने के बाद सोने की आभूषण रखड़ी सेट, कानों के टॉप्स, बच्चे की टॉप्स जोड़ी, चांदी की पायजेब और २५ सौ रूपए की नगदी चुरा ले गए। वक्त घटना घर सूना था। बनाड़ पुलिस ने मौका मुआयना कर अब चोरों की तलाश शुरू की है।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण पर चर्चा २६ को

जालोर,(कासं)। जिले में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्य की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समिति के अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में २६ मई को दोपहर १२ बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) डॉ. धनसिंह राजपुरोहित ने यह जानकारी दी।

कार्यालय नगर परिषद, जैसलमेर (राज.) - ३४५००१

क्रमांक/भूमि /२०२५-२६/२४४

-:: सार्वजनिक ई -नीलामी सूचना ::-

दिनांक : ०६.०५.२०२५

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि जैसलमेर शहर में आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों उनके निम्न सामने अंकित तिथि को ऑनलाईन माध्यम से नीलामी राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम १९७४ के अनुसार ९९ वर्ष की लीज होल्ड के आधार पर की जायेगी । इच्छूक क्रय कर लाभ उठायें । उक्त वैचान पर राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम १९७४ के समस्त व समय –समय पर जारी परिपत्र लागू रहेंगे ।

क्र.स.	स्थान का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड साईज (प्रति भूखण्ड)	बोली प्रारंभ राशि	रिजर्व प्राईज केवल लीज/अरबन असेशमेन्ट गणना हेतु	नीलामी आरंभ तिथि	धरोहर राशि पत्येक भूखण्ड
१.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	A-59६,5९५,5९४,5९३,5९०,5८९,5८८,5६३	252sq.mtr	16,26,६00/-	8,८१,075/-	1५.०५.२02५ to २०.०५.२02५	32,532/-
2.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	A-61९,B-526,530,52५,५१८,C-89,8८,86	216sq.mtr	13,९४,400	७,५५,३00/-		27,888/-
3.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	A-85,84,83,D-1	112.50sq.mtr	7,26,000/-	3,९3,250/-		14,520/-
4.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	B-1८,१७,१६,१५,१४,१३,१२,११,९,D-488,229,223,१८९,१७१,१७0	90sq.mtr	5,80,800	३,१४,६00		११,६१६/-
5.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	B-339,33८,३२7,316,275,264,263,254,252	75sq.mtr	4,84,200/-	2,62,275/-		9,684/-
6.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	D-45	162sq.mtr	10,45,800/-	5,66,475/-		20,916/-
7.	श्री गोवर्द्धनदास कल्ला आवासीय योजना जैसलमेर	A-7१6,7१3,६८८,६८८,६८7,६८६,६८५,६८१,६८०,६७९,६७८,६७७,६१८,६१४,६१२,५७६,५७५,५७४,५७३,५६५,५२२,५१८,५०९,४७९,४७६,२८९,२८८,२८७,२८६,२८५,२३१,२३०,२२९,२२८,११४,११३,१११,३७,३६,३३,२९,२७,२६,१२0,११२,B-५१७	324sq.mtr	20,९१,६00/-	११,३२,९५0/-	2१.०५.२02५ to २६.०५.२02५	4१,832/-
8.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक भूखंड)	सुथार समाज के पास व्यवसायिक क्षेत्र	200x130 sq.ft	५,७७,७२,000/-	१,04,00,000	27.०५.२02५ to ०२.०६.२02५	11,५५,४४0/-
9.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक भूखंड)	जी ब्लॉक के पास	90x100	१,99,98,000/-	36,00,000/-		3,99,960/-
10.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक भूखंड)	एफ ब्लॉक चौराहे के पास	130x130	3,७५,५१,८00/-	67,60,000/-		७,५१,036/-
1१.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक भूखंड)	पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड	200x300 sq.ft	13,३३,२0,000/-	2,40,00,000/-		26,66,400/-
12.	जवाहर लाल नेहरु आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक भूखंड)	भील समाज छात्रावास के पास	13466.25 sq. ft	2,24,३४,७७2/-	43,७६,५३१/-		4,48,69५/-
1३.	जवाहर लाल नेहरु आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक दुकानें)	जैन दादाबाडी (प. जवाहर लाल नेहरु कॉलोनी)S-१ to S-20 Shops	15x30	7,49,700/-	१,46,250/-	0३.०६.२02५ to 09.०६.२02५	14,994/-
14.	जवाहर लाल नेहरु आवासीय योजना जैसलमेर (वाणिज्यिक दुकानें)	भील समाज छात्रावास के पीछे १ to 9	10x50 sq.ft	8,33,000/-	१,६2,५00/-		१६,६६0/-
1५.	गांधी कॉलोनी विस्तार आवासीय योजना जैसलमेर	7९७	25x50 sq.ft	18,75,000/-	6,93,750/-		37,500/-
1६.	रेलवे स्टेशन के सामने (सिनेमा हेतु भूखण्ड)		80x१50 sq.ft	4,20,00,000/-	72,00,000/-		8,40,000/-
1७.	रेलवे स्टेशन जैसलमेर निर्मित दुकान	Shop No. 5	10x20 sq.ft	7,00,000/-	१,20,000/-		14,000/-
18.	होटल कॉम्पलेक्स बाडमेर रोड जैसलमेर वाणिज्यिक दुकान	S-3,५,११,१५,२४,२७,२८,२९,३0,३१,36,39,५4	20x40 sq.ft	4,40,000/-	3,60,000/-	१०.०६.२02५ to १६.०६.२02५	8,८00/-
19.	होटल कॉम्पलेक्स बाडमेर रोड जैसलमेर वाणिज्यिक दुकान	S-143,१45,१46,१47,१५२,१५३,१५४,१५७,१६0,१६१,१६२,१६३,१६४,१६५,१६७,१६८,१६9,१७१,१७२,१७४,१७५	10x20 sq.ft	१,१0,000/-	90,000/-		2,200/-
20.	बबर मगरा खुडी रोड आवासीय योजना जैसलमेर	29,30,32,33	40x60 sq.ft	19,20,000/-	4,80,000/-	1०.०६.२02५ to १६.०६.२02५	38,400/-
2१.	बबर मगरा मुख्य सड़क के अंदर की तरफ वाणिज्यिक भूखंड	वाणिज्यिक भूखंड : - १	85x85 sq.ft	50,00,000/-	28,90,000/-		१,00,000/-
22.	इंद्रा नगर आवासीय योजना जैसलमेर	68३,६90	20x49 sq.ft	25,00,000/-	4,90,000/-		50,000/-
23.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर	A-271,272,273,274,275	50x90 sq.ft	50,00,000/-	18,00,000/-		१,00,000/-
24.	लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना जैसलमेर	E-52	25x50 sq.ft	13,00,000/-	5,00,000/-		26,000/-
25.	जवाहर लाल नेहरु आवासीय योजना जैसलमेर	C-889	30x60 sq.ft	15,00,000/-	5,85,000/-		30,000/-
2६.	जवाहर लाल नेहरु आवासीय योजना जैसलमेर	B-१७७	40x70 sq.ft	25,00,000/-	9,१0,000/-	१७.०६.२02५ to २३.०६.२02५	50,000/-
27.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	B-155,१52,१५१,१35,23, C-226,१७७, 152,१36,85,60,५7,48,42	1800 sq.ft	7,20,000/-	5,85,000/-		14,400/-
28.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	C-59	2400 sq.ft	9,60,000/-	7,80,000/-		19,200/-
29.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में वाणिज्यिक भूखंड (दुकान)	G-११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९, 20,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९, 30,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८	20x40 sq.ft	6,40,000/-	2,60,000/-		12,800/-
30.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	G-39,40,4१,४२,43,44,45,46,47, 48,49,५0,५१,५2,५३,५४,५५,५६,५७, ५८,59,60,6१,६2,६3,६4,६५,66	12x20 sq.ft	१,92,000/-	78,000/-		3840/-
3१.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	G-67,68,69,७0,७१,७२,७३,७4,75, 76,७७,७८,७9,80,8१,82,8३,84,85, 86,87,88,89,90	20x40 sq.ft	6,40,000/-	2,60,000/-	१७.०६.२02५ to ३०.०६.२02५	12,800/-
32.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	G-9१,92,93,94,95,96,97,98,99, 100,१0१,१02,१03,१04,१05,१06	20x40 sq.ft	6,40,000/-	2,60,000/-		12,800/-
33.	सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना	B-155,१52,१५१,१35,23, C-226, १77,१५2,१36,85,60,५7,48,42	1800 sq.ft	7,20,000/-	5,85,000/-		14,400/-
34.	भुआसा मंदिर गौशाला के पास वाणिज्यिक योजना निर्मित दुकान	Shop No. 5,6,7	10x20 sq.ft	9,00,000/-	4,१८,000/-		18,000/-
35.	ग्रामीण बस स्टैंड न्यू डेडानसर रोड योजना जैसलमेर निर्मित दुकानें	Shop No. 19,20	१6.१0x३2.06 sq.ft	20,00,000/-	3,09,700/-	24.०६.२02५ to ३०.०६.२02५	40,000/-
3६.	ग्रामीण बस स्टैंड न्यू डेडानसर रोड योजना जैसलमेर निर्मित दुकानें	Shop No.21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,३१,३2,३3,३4,35	15x30 sq.ft	20,00,000/-	2,70,000/-		40,000/-

नियम एवं शर्तें :-

१.भूमि निष्पादन नियम १९७४ व संशोधित नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
२. नगर परिषद जैसलमेर को निलामी में प्राप्त बोलियां स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
३. नगर परिषद जैसलमेर को निलामी में पर्याप्त राशि प्राप्त नही होने की स्थिति में बोली की अंतिम तिथि बढ़ाने या निलामी अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
४. सफल बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृति की दिनांक से मांग पत्र जारी होते ही तीन कार्य दिवसों के भीतर १५ प्रतिशत बोली की राशि जमा करानी होगी अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
५. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि की ३५ प्रतिशत नीलामी की तिथि से १20 दिन के भीतर जमा करानी होगी।6. सफल बोलीदाता को शेष ५0प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से १80 दिवस के भीतर जमा करानी होगी।
७. यदि सफल बोलीदाता नीलामी तिथि से १५ दिवस के भीतर पूरी राशि जमा कराता है तो उसे बोली राशि पर १ प्रतिशत छूट दी जावेगी ।
८. बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण बोली राशि जमा नही कराई जाती है तो धरोहर राशि सहित १५ प्रतिशत प्रारंभिक जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और भूखण्ड की बोली स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
9. इन भूखण्डों पर निर्माण कार्य नियमानुसार स्वीकृति परिषद से प्राप्त कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार जैसलमेर शैली में करवाना होगा।
१०. नीलामी शर्तों व नियमों के उल्लंघन पर भूखण्ड विक्रय निरस्त किया जा सकेगा।
११. भूखण्ड नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं नियम हेतु https://lsgeauction.rajasthan.gov.in/ में देखे एवं अवलोकन किये जा सकते है।
१२. भूखण्ड का कब्जा/शास्वत लीज डीड/ लीज राशि समय पर जमा कराने का दायित्व सफल बोलीदाता का रहेगा।
१३. असफल बोलीदाता की धरोहर राशि वापसी योग्य (Refund) होगी जो निलामी की समस्त प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात स्वतः असफल बोलीदाता के निलामी में पंजीकृत खाते में स्वतः जमा की जायेगी।
१४. नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in/ पर जाकर Log in ऑप्शन पर क्लिक करके स्वयं की SSO ID बना ले व जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में SSO ID प्रयोग में ली जा रही है वे SSO ID के माध्यम से Log in कर LSG E- AUCTION ऑप्शन पर क्लिक करके बोली में भाग ले सकते है। वेब साईट पर रजिस्टर करने सम्बन्धी असुविधा एवं इस सम्बन्ध में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हैल्पडेस्क नम्बर 7878१7१00७ एवं 8५६2007843 पर सम्पर्क करें।

(लजपाल सिंह)	(परसाराम आर्. ए.एस)
आयुक्त	प्रशासक
नगर परिषद, जैसलमेर	नगर परिषद, जैसलमेर

ट्रक कंटेनर में ले जाया जा रहा 1.48 करोड़ रुपये का 300 किलो गांजा पकड़ा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने टोंक में कार्रवाई की

टोंक/जोधपुर, (कासं)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टोंक में कार्रवाई करते हुए करीब तीन सौ किलो गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1.48 करोड़ रुपए बताई गई है। गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीबी की संयुक्त टीम ने 19 मई की रात को टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

एनसीबी के जोनल निदेशक (जोधपुर-जयपुर) आईआरएस घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर एनसीबी के पास महत्वपूर्ण इनपुट था और उसी आधार पर एनसीबी की टैक्निकल सर्विलांस यूनिट लगातार उस पर काम कर रही थी। टीम को पुछ्छा जानकारी मिली, तब संयुक्त टीम ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर को रुकवाया। जब इसकी बारीकी से तलाशी ली गई, तो उसमें एक विशेष रूप से निर्मित छुपा हुआ कक्ष मिला जिसमें 290 पैकेटों में कुल



एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह चालक को गांजा सहित गिरफ्तार किया।

296.204 किलोग्राम गांजा छुपाकर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह-चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके

अलावा नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी धर दबोचा।

जोनल निदेशक घनश्याम सोनी के अनुसार इस ऑपरेशन में टोंक और सीकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने

भी अहम भूमिका निभाई। अब गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों से तस्करी के इस नेटवर्क की गहराई तक जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

■ ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया, नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी दबोचा

■ एनसीबी ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर में गांजा पकड़ा

एनसीबी के जोनल निदेशक सोनी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए एनसीबी का सहयोग करें। यदि किसी के पास नशीले पदार्थों से जुड़ी कोई सूचना हो, तो पोर्टल एमएनएस या 1933 हेल्पलाइन नंबर पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकता है। सूचनाकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में हालोको अपराधी मोंटू कंडार को खिलाफ यौन शोषण और धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब अग्रिम जांच आरंभ की है। उसका मेडिकल करवाया गया है। थानाधिकारी ईश्वरचंद पारिक ने बताया कि हाईकोर अपराधी नागरी गेट निवासी मोंटू कंडारा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि वह यहां एक स्थान पर किराए पर रहती है। वह उसके संपर्क में आई तब उसने शादी का झांसा देकर पिछले दो साल से यौन शोषण करता रहा। शादी का दावा बनाए जाने पर वह धमकाने लगा और मारपीट की। थानाधिकारी पारिक ने बताया कि पीड़िता का आज मेडिकल करवाया गया है।

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी की हत्या के फरार आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था। जोधपुर पुलिस जिला पश्चिम के टॉप-10 वांछितों में शामिल है। कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी हमीरसिंह भाटी ने बताया कि आरोपी कानाराम को जयपुर से पकड़ा है। वह प्रॉपर्टी व्यवसायी चंदन सिंह की मार्च में हत्या कर भागा था। आरोपी जयपुर से होते हुए अहमदाबाद गया। उसके बाद बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में 8-10 दिन रहने के बाद जयपुर आ गया और मजदूरी करने लग गया। पुलिस को इस बारे में भनक लगी तो टीम गठित कर जयपुर से दबोचा। जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2025 को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी में

■ प्रॉपर्टी व्यवसायी चंदन सिंह की मार्च में हत्या कर भागा था आरोपी, बेंगलुरु में 8-10 दिन रहने के बाद जयपुर आ गया और मजदूरी करने लग गया

■ आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था और जोधपुर पुलिस जिला पश्चिम के टॉप-10 वांछितों में शामिल था

भवानी सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में भवानी सिंह ने बताया कि 21 मार्च को मेरा भाई चंदन सिंह पुत्र हनुमान सिंह के साथ रात्रि में करीब 12 बजे से 12.40 बजे के आसपास रूपेश के मोबाइल पर मुकेश हुड्डा ने बात की और बताया कि आपकी गाड़ी में मेरा मोबाइल गिर गया था। आप मेरा मोबाइल मुझे लाकर दो, नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे। तभी फोन गंगाराम ने अपने

पास लेकर फोन पर चंदन सिंह की धमकी दी। कहा कि मेरे दोस्त मुकेश हुड्डा फोन आपकी गाड़ी में भूल गया है, उसे वापस कर दो नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे और तुझे मार देंगे।

चंदनसिंह फोन देने के लिए घर से रवाना हुआ। तब मोती मार्केट पुलिया के नीचे पहले से रूपेश सैन, मुकेश हुड्डा, गेनाराम, पारस सैन व 2-3 अन्य लोगों ने चंदनसिंह पर धारदार हथियार से

हमला कर दिया। चंदनसिंह के गर्दन के पास से खून बहना शुरू हो गया। चंदनसिंह का भाई हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी रूपेश सैन, पारस सैन, अर्जुन चौधरी व प्रतापराम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्य आरोपी मुकेश हुड्डा व अशोक चौधरी, गंगाराम को गिरफ्तार किया गया था। कानाराम जाट फरार चल रहा था। उसको अब जयपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। कानाराम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम में कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी, हैड कॉन्स्टेबल प्रेम चौधरी, गेनाराम, पारस सैन व 2-3 अन्य लोगों ने चंदनसिंह पर धारदार हथियार से

पचास लाख की पंजाब निर्मित शराब पकड़ी, दो जने गिरफ्तार

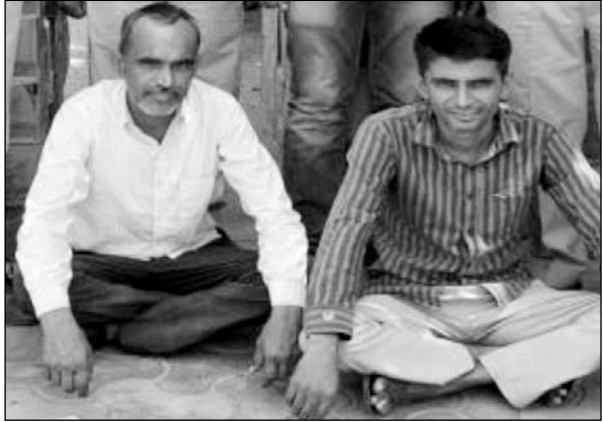
जालोर, (कासं)। जालोर जिले के सायला पुलिस ने गुरुवार को सरहद सांगाणा स्थित एक्सप्रेस- वे टोल नाका के पास ट्रक डम्पर को जब्त कर पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 414 कार्टून बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है।

महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार जोधपुर, रेंज जोधपुर के द्वारा रेंज में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु “ऑपरेशन भौकाल” के तहत

■ आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया

कार्यवाही करने के निर्देशानुसार मन ज्ञानचन्द्र यादव, जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशानुसार जिले में शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत हाइवे नाकाबंदी, संदिग्ध स्थानों एवं वाहनों की सघन तलाशी ली जाकर जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाहीयों की जा रही है।

इसी क्रम में मोटाराम गोदारा अति. पुलिस अधीक्षक, जालोर एवं



सायला पुलिस ने अवैध शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गौतम कुमार जैन पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त जालोर के सुपरविजन में सुरेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला के नेतृत्व में महिपालसिंह उपनिरीक्षक मय जाब्जा की पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचनानुसार अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे सरहद सांगाणा स्थित टोल नाका के पास पहुंच कर हड़मनाराम पुत्र रामाराम विशनोई निवासी नया वास, मेघावा, पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर व नैनाराम पुत्र महिराम विशनोई निवासी विशनोईयो का वास, किसको सप्लाई किया जाना था इस सम्बंध में गहन अनुसंधान जारी है।

पाली के कब्जे से ट्रक में भरी हुई पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना सायला में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया है, माल पंजाब से मंगवाकर गुजरात सप्लाई करने वाले पूनमाराम निवासी हेमागुड़ा के घर पर दबिश दी गई जो घर पर नहीं मिला। अवैध शराब पंजाब से कहां से भरवाया गया तथा गुजरात किसको सप्लाई किया जाना था इस सम्बंध में गहन अनुसंधान जारी है।

सांप के काटने से बालिका की मौत

भीलवाड़ा, (निस्)। जिले के काछोला थाना क्षेत्र में घर पर सोई हुई सात साल की मासूम बालिका को नींद में गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां मासूम ने बीती रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मानवी पिता हेमराज दरोगा मूलतः चित्तौड़ जिले के निवासी हाल काछोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में अपने परिवार के साथ रह रही थीं। मासूम आंगनबाड़ी में पढ़ाई करती थीं। रोजमर्रा की तरह मानवी घर पर ही अपने माता-पिता के साथ सो रही थीं, इसी दौरान सांप ने सोते समय मानवी के दोनों हाथों पर काट लिया जिसके चलते मानवी की हालत बिगड़ गई। सांप के काटने से मानवी चिल्लाई तो तुरंत माता-पिता उसे नजदीकी चिकित्सालय ले गए, जहां से हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे तुरंत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।

एमजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान बुधवार रात मानवी ने दम तोड़ दिया, जिसके शव को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवर्जनों को सुपुर्द कर दिया गया।

129 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के तीन युवक गिरफ्तार

उदयपुर, (निस्)। शहर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ठगी में काम आने वाले उपकरणों को जब्त किया। आरोपियों ने देशभर में 719 प्रकरणों में 129.72 करोड़ की ठगी की है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान 21 मई को डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्न को सूचना मिली कि सबसिटी सेंटर हिरणमगरी में कार में सवार तीन लड़के अन्य व्यक्तियों से बैंक खातों से अवैध लेनदेन कर रहे हैं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश

■ ठगी करने में सहयोगी उपकरण जब्त, आरोपियों के खिलाफ देशभर में 719 शिकायतें दर्ज हैं

ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में श्यामसिंह रत्न स्पेशल टीम प्रभारी मय टीम व हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी मय टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करते हुए हर्षवर्धन झा पुत्र राजेश झा, जयेश कुमार खटीक पुत्र सेशचन्द्र खटीक एवं तुकानसिंह पुत्र ब्रजेंसिंह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 मोबाइल, 2 लेपटॉप, 7 कंपनियों

की मोबाइल सीम, 10 एटीएम, चैकबुक, बैंक डायरी सहित वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर प्रकरण दर्ज कर जांच हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी को सौंपी है। आरोपी टेलराम गुप्त के माध्यम से केवाईसी को ड्रेगन एसएमएस व गो एसएमएस नाम की एप्लीकेशन के माध्यम सेओटीपी प्राप्त कर पूरा एक्सेस देते थे। खातों की जानकारी प्राप्त करने के अपूर्ण खातेधारकों को लालच देकर केवाईसी पूर्ण कर उसके मोबाइल नंबर को लिंक कर खाते की संपूर्ण जानकारी, बैंक डायरी, चैक बुक व खाते की जानकारी भेजी जाती थी, जिनमें ठगी की नकदी जमा होती थी।

एसडीएम के लिए 70 हजार की रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार

लघु ईट-भट्टा लगाने के लिए भूमि समपरिवर्तन निरस्त करने के लिए परिव्रादी से रिश्वत ली

बहरोड़/नीमराना, (निस्)। जिला कोर्टपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ उपखंड अधिकारी के रीडर ललित कुमार यादव निवासी गादोज तहसील बहरोड़ को एसडीएम रामकिशोर मीणा के नाम से लघु ईट-भट्टा लगाने के लिए भूमि सम परिवर्तन निरस्त करने के लिए परिव्रादी से 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसबीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के

महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसबीबी एसयू द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी परिव्रादी को परिव्रादी की भूमि पर लघु ईट-भट्टा लगाने के समपरिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिये 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसबीबी जयपुर द्वितीय एवं अनिल कयाल उप महानिरीक्षक

पुलिस के सुपरबीजन में एसबीबी एसयू द्वितीय के प्रभारी अधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में मय विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी ललित कुमार यादव हाल वरिष्ठ सहायक रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ जिला कोर्टपूतली बहरोड़ एसडीएम रामकिशोर मीणा के लिए 70 हजार रुपये के जगत गंग बंगला की ड

महिलाओं के जेवर लूटने वाले दो गिरफ्तार

उदयपुर, (निस्)। रात के समय सो रही महिला के सोने के जेवरार लूट ले जाने वाते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पांच वारदातें कबूल की।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि 5 मई को रात के समय अभियुक्त बंशीलाल उर्फ बंटी पुत्र खेमा मीणा निवासी बनकड़ा कुराबड़, प्रकाश उर्फ पिन्टू उर्फ अंतक मीणा पुत्र जीवनलाल मीणा निवासी डांग फला उमरड़ा हॉल डेड किया हिरणमगरी कुराबड़ के जगत गंग बंगला की ड ाणी में सो रही शांतिबाई पत्नी भेरूलाल रेबारी के कानों में पहनी सोने के कर्णफूल व छोड़ी लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में कुराबड़ थानाधिकारी प्रभुलाल के नेतृत्व में गठित दल ने बंशीलाल उर्फ बंटी पुत्र खेमा व प्रकाश उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में वारदात में महेश पुत्र बाबुलाल उर्फ दलपत मीणा निवासी मानपुरा के शामिल होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात करने से पूर्व चोरी की गई बाईक व एक बाईक का इंजन भी बरामद किया। पुलिस आरोपियों ने पूछताछ कर रही है।

व्यापारी से 1.74 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से धोखाधड़ी की थी

भीलवाड़ा, (निस्)। जिले की सायबर थाना पुलिस ने दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से 1.74 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 48 लाख 39 हजार रुपए भी रिकवर कर लिए हैं। उक्त फर्म के खिलाफ देश के पांच राज्यों में शिकायत दर्ज होने का भी खुलासा हुआ है।

सायबर पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी व्यवसायी से गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई सायबर ठगी को लेकर सायबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बैंक एवं नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 60 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवा दिये। पुलिस टीम ने अथक प्रयास कर प्रकरण में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी



भीलवाड़ा जिले की सायबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

करने वाले आरोपियों सरताज अली तथा मो. अख्तर अंसारी को गिरफ्तार

किया था। अभी तक पुलिस 48.39 लाख रुपये पीड़ित व्यवसायी को बैंक

खाते में रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के रहने वाले

Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd. Head Office : Near Hardav Joshi Circle, Jalore (Rajasthan) Email: headoffice@jalsahakari.com Bank Branch : www.jalorsahakari.com Phone No. 9413854111	
क्रमांक/आवृत्तिकांक/1911	दिनांक: 22.05.2025
निविदा सूचना जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए वर्ष 2025-26 COMPUTER, HARDWARE- SOFTWARE, UPS - Battery & ATM/ Recycler Machine इत्यादि खरीद हेतु इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) अपनी निविदा एवं सीलबत विभाजन के दिनांक 06.06.2025 को सां.वि. 4 बजे तक बैंक प्रभार कार्यालय स्थित मुख्यालय पर अधिकारी के कक्ष में रखी गये टेंडर बॉक्स में सहान सुनिश्चित करें। निविदा प्रति निविदा शुल्क जमा करवाते पर प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत विवरण, जर्नल, माना इत्यादि के सम्पूर्ण जानकारी बैंक की वेब साइट www.jalorsahakari.com पर उपलब्ध है।	
UBN No.: RSI25265LOB00008	पूरानाम नम्बर
Raj.Samwad/C/24/2818	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD. NOTICE INVITING BID NIB Number: 08/2025-26 Bids are invited for the Procurement of Services of "Strategic Business Promoter to Equip, Operate, Manage & Transfer Business Services at ICD, Jodhpur" from the eligible and experienced bidders up to 5.00 PM on 05.06.2025 Other particulars of the bid may be viewed on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in , https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state and the official website of RSIC i.e. https://www.industries.rajasthan.gov.in/rsic/ The approximate value of the procurement is INR Rs. 15.00 Crores UBN No.: RSI25265LOB000081, JOD2526WSOB000082 Raj.Samwad/C/24/2818	
क्रमांक :- जीएआर/2025-26/471	दिनांक :- 20/05/2025
ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/09/2025-26 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 4 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो जो निविदा की निमात्रित शर्तों को पूर्ण करती है जो निमात्रित प्रपत्र में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा भेजे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jodhpurjda.org , www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। UBN No.: JOD2526WSOB000081, JOD2526WSOB000082 रज.समवाद/सी/25/2756	
अधिरात्री अधिकृतता	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर क्रमांक:- अन्व.वि.खण्ड/सा.नि.वि.खण्ड/2025-26/126 दिनांक:- 14.05.2025 ई-निविदा सूचना संख्या 06/वर्ष 2025-26 (NIB Code No. PWD2526A0574) निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतकारण कार्यों के लिए मोहरबन्द निविदाएं सा.नि.वि.खण्ड में पंजीकृत एवं पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रयत्नों की प्रति अधोस्तराक्षरकार के कार्यालय में निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक 15.05.2025 से 26.05.2025 तक सां.वि. 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 27.05.2025 को दोपहर 15.00 बजे छोली जायेगी। प्री-बिड मीटिंग की दिनांक 21.05.2025 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्तें एवं स्थितियों तकनीकी आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्तें व विवरण इस कार्यालय में व बीपीआर की वेबसाइट www.dipronline.org , http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। कुल कार्यों की संख्या 03 कुल लागत 293.61 लाख।	
UBN No. 1. PWD2526WSOB01728 2. PWD2526WSOB01729 3. PWD2526WSOB01730 DIPR/C/6491/2025	भवदीय (शैलेश कुमार पाठक) अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड राजाखेड़ा क्रमांक: 182-196 दिनांक: 14.05.2025 अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02 / 2025 - 26 NIB Code : PWD2526A0565 and UBN is : PWD2526WSOB01708 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड राजाखेड़ा जिला बीकानेर में सड़क एवं पुलिया मरम्मत कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों, राज्य सरकार के अन्य विभागों में पंजीकृत "एए", "ए", "पी" "सी" एवं "डी" श्रेणी संवेदकों एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे स्थापना में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए", "पी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निमात्रित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट www.eproc.dipronline.org व http://www.pwd.rajasthan.gov.in , www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।	
क्र. सू. मुख्यालय का नाम सं.	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजाखेड़ा क्र. सू. निविदा का कार्य रु.
1. निविदा का कार्य 2. निविदा को कुल लागत	1. पुलिया मरम्मत कार्य रु. 17.25 लाख
3. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की प्रक्रिया	1. वित्त विभाग द्वारा जारी प्रपत्र प.5 (घ)/वित्त/सावितेवि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-सम चालान पर ऑनलाइन एक ही चालान द्वारा निम्न बजट पर में जमा करानी है। (1) निविदा शुल्क 0075-00-800-52-01 (2) प्रोसेसिंग शुल्क 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (RI/SI.Fees) (3) धरोहर राशि 8443-00-108-00-00
4. निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तारीख (वेबसाइट पर)	1. दिनांक 15.05.2025 प्रातः 9.30 बजे दिनांक 26.05.2025 सां.वि 6.00 बजे तक
5. निविदा फार्म जमा करने की तारीख (वेबसाइट पर)	1. दिनांक 15.05.2025 प्रातः 9.30 बजे दिनांक 26.05.2025 सां.वि 6.00 बजे तक
6. निविदा खोलने की तारीख (वेबसाइट पर)	1. दिनांक 27.05.2025 दोपहर 12.30 बजे
DIPR/C/6480/2025	

(सौरभ शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड, राजाखेड़ा

मोतीलाल मीणा ऑयल
इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र
डायरेक्टर नियुक्त

परिक्षाओं में डमी और फर्जी डिग्रियों की समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार से विभागाध्यक्ष द्वारा कक्षा वर्षों में हुई भर्तियों में कार्मिकों के कर्मी और से 6 जून 2024 को राज्य सरकार के समस्त विभागों को पत्र जाते जाते गत 5 वर्ष में हुई भर्तियों के कार्मिकों के ज्ञान के संबंध में लाक्षा गया। इसी के संकेत के रूप में निदेशक माध्यम शिक्षा विभाग राज्यधानी बोकानेर द्वारा अनुवृत्त के कमेटी गठित की गई थी। जिस पर एफओसी राज्यधानी जयपुर द्वारा अब तक 65 कार्मिकों के विरुद्ध सत्यापन के आधार पर 4 प्रकरण पंजीबद्ध किये है। यह प्रकरण में व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018-19, 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ लेवल-1 भर्ती परीक्षा 2018-19, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018-19, शारीरिक शिक्षा डाटा-टोआई भर्ती परीक्षा 2018 व 2022, पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2018, शारीरिक प्रशिक्षण अनुश्रवक भर्ती परीक्षा 2018, अध्यापक लेवल- विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 और अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है। भविष्य में विभागाध्यक्ष गठित समितियों द्वारा अपनी कार्यवाही सत्यापन के दौरान संदिग्ध पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी जांच की जाएगी एवं दोषी पाये जाने पर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस कमिश्नर
आज झोटवाड़ा थाने
में करेंगे जनसुनवाई

विविध लाइनों को भूमिगत केबल के माध्यम से स्थानांतरित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसमें शामिल है इयाना से अधिकांश कार्य को संपन्न हो चुके हैं एवं शेष कार्य तीव्र गति से करवाया जा रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्र विनयवर्मा-विस्तार में विचित्री वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 1700.55 कोरों के अंशों के लिए लागत से 7.25 किलो सड़कों को काट दिया जाएगा। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का उपयोग उन्नत तथा 3.20 किलो मीटर की नालियों का आरसीसी बॉक्स टाइप संरचना द्वारा उपयोग किया जा रहा प्रस्तावित है। इसके अलावा भी क्षेत्र में सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चौराहों पर ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है तथा अन्य चिह्नित सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है।

अवैध हथियार
सहित दो बदमाश
गिरफ्तार

है। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक दृष्टता के चलते कोई भी निर्णय आइए दर्ज करवाई नहीं। जिसमें यह कहा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर न्यायाधीशों लगाते हुए पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

गौरतलब है कि सवाई माधोपुर के बीतली में करीब दो साल पूर्व भीमवार अंडेकर की प्रतिमा में अनावरण हुआ था। जिसकी शिलालेखायास पट्टिका में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी नाम था। अंडेकर जयंती से पहले विधायक इंदिरा और मंडल अध्यक्ष हनुमत् के बीच इस नाम पट्टिका को लेकर विवाद हुआ था। एमएलए के समर्थकों ने कहा है कि हनुमत् दीक्षित ने नाम पट्टिका से विधायक का नाम हटा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मौके पर पहुंची थी। जहां दोनों के बीच हाथापाई हुई थी।

कार सवार बदमाशों ने किया इंजीनियरिंग छात्र का अपहरण

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिलीं
10 दुर्लभ पाण्डुलिपियां

जयपुर। आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध को एक नई दिशा देने वाला आशम अकादमी द्वारा हाल ही में जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्राप्त हुआ है। संस्थान के फुटेजवे पाण्डुलिपि विज्ञान विभाग को अनेकहपुर (सीकर) स्थित श्री सरस्वती पुस्तकालय से 10 अर्घ्यतुल्य और ऐतिहासिक आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियाँ अध्ययन एवं शोध के लिए प्रदान की गई हैं।

विभागाध्यक्ष प्रो. असित कुमार याज्ञा ने बताया कि प्राप्त पाण्डुलिपियाँ नैत्राचार्य, रस्तारिणी, गम्बरकप प्रभृति विद्वान् हस्तलिखित और संतान प्रयोगात्मक चरित्र जै से बहुमूल्य ग्रंथ शामिल हैं। इन पांडुलिपियों का ऐतिहासिक और चिकित्सीय महत्व अपार है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनेक रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।

करने की जगह मोबाइल को लेकर बैठ
गया। मोबाइल मॉर्गने पर दोनों लड़कों ने
नारापीठ कर कार में डालकर उसका
अपहरण कर लिया। अपहरण कर ले जान
के दौरान चतुर्ती कार से प्रिंस मीणा ने शोर
मचाया तो इसकी मदद के लिए इक्कड़
एक लोगो ने चले कर का पीछा करने पर
अपहरणकर्ताओं ने चले कर का से प्रिंस
को धक्का देकर रोड पर फेंक दिया। लोगो
ने पीछा कर घेरादीदी कर कार को
मकड़कर रुकवा लिया। सूचना पर पहुंची
प्रिंस ने दोनों आरोपियों को राउंडअप
कर कर को जन्त किया। अपहरण कर
कड़ड़े आरोपी मोहित मीणा और उसके
बर्नाबालिग दोस्त ने छुटाछाड़ में मौज-मस्ती
के लिए रुपय वसूली के लिए अपहरण
करना बताया है।

जयपुर। पिंक सिटी मिल्स (पीसीएम मसाले), जयपुर की वार्षिक आम बैठक का आयोजन आज कंपनी मुख्यालय पर किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कंपनी के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक एल. गुप्ता और संस्थापक सदस्य किशन अवतार खंडेलवाल ने की। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य द्रोपती देवी, माया देवी खंडेलवाल तथा निदेशक अमित खंडेलवाल एवं अंकित खंडेलवाल सहित अन्य आठ बौद्ध सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में एल. एल. गुप्ता एवं किशन अवतार खंडेलवाल ने जानकारी दी कि कंपनी को भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा करते हुए 5.8 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीसीएम मसाले राजस्थान की पहली एमार्क प्रमाणित मसाला निर्माता कंपनी है, जो 80 से अधिक प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है। कंपनी के निदेशक अमित खंडेलवाल एवं अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पीसीएम ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पादों की आपूर्ति शुरू की है। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द ही इंस्टेंट ड्राई ग्रेवी और इंस्टेंट चटनी के और भी नए उत्पादों की श्रृंखला लॉन्च करने की योजना बना रही है। संस्थापक सदस्यों द्रोपती देवी और श्रीमती माया देवी खंडेलवाल ने बताया कि कंपनी की “केजो रिलेस योजना” इस माह के अंत तक समाप्त हो रही है, जिसे देशभर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। साथ ही, कंपनी ने नवीनतम तकनीकी से युक्त नई रिसेचो एप्लीन योजना भी क्रियान्वित की है, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी। कंपनी निकट भविष्य में बड़े स्तर पर विस्तार की योजनाएं लेकर आ रही है।

एक्शन ऑपरेशन नगर (आग) के तहत पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने कानोता थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्टल बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन कंवराया ने बताया कि ऑपरेशन एक्शन ऑपरेशन नगर (आग) के तहत सीएसटी ने कानोता थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार देशी पिस्टल रखने वाले आरोपित कृष्ण कुमार शर्मा (35) निवासी कानोता जयपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल जप्त की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह अवैध हथियार उसकी मौसी का लड्डे की जेबिश शर्मा उर्फ जीतू निवासी गुर्जर की थडी महेश नगर ने उसे रखने के लिए दी थी और इस अवैध हथियार के साथ दो कारसू भी थे, जिनका 10 मई को उसके जन्मदिन पर फायर कर दिए गए।

सार-समाचार

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर चर्चा

पाली, (नि.सं.)। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देशानुसार आज गुरूवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ बजरंग सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुयी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ बजरंग सिंह ने कहा कि मानसून से पहले की जाने वाली मानसून के समय होने वाली व अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सभी संबंधित विभाग आवश्यक प्रबन्ध व तैयारी कर ले जिससे कि मानसून के समय होने वाली दुर्घटनाओं से आमजन का बचाव किया जा सके। बैठक में उन्होंने एजेन्डानुसार सभी बिन्दुओं पर जानकारी ली जिनमें विभिन्न विभागो एनएचएईआई, एनएच , नगर निगम आदि द्वारा मार्गो पर निराश्रित पशुओं को हटाने व अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही अवेध कट्स बंद करने, साथ ही आने वाले बारिश के सीजन के लिये सडकों और शहर के सडकों में सुधार की जानकारी, सडकों की स्थिति व मरम्मत कार्य, दुर्घटनाओं की डाटा एन्ट्री रिपोर्ट, एक्सीडेन्ट स्मॉटस के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने हेलमेट का उपयोग व आमजन में जागरूकता के लिये शिक्षा विभाग को और हेलमेट का प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिये। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा समिति के सचिव सार्वजनिक विभाग के एसई दिलीप परिहार ने सभी विभागों से श्री मानसूत में आवश्यक तैयारी करने व सुझाव समस्याओं को पर चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी ने सभ्य, नगर निगम आयुक्त नवीन भादड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई दिलीप परिहार, एसाटीओ गणपत पुनर, जिला परिवहन विभाग व शिक्षा , पालयत चिकित्सा विभाग व सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे।

स्मार्ट अनुबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

जोधपुर, (कासं)। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं सार्वजनिक वितीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (राजस्थान सरकार) के संयुक्त तत्वावधान में अनुबंध प्रारूपण और अनुबंध प्रबंधन प्रणाली (स्मार्ट अनुबंध, सरकारी खरीद) पर आधारित दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरूवार को विश्वविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के प्रमुख विभागों शिक्षा, लोक निर्माण, चिकित्सा, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि से कुल 42 वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी सहभागी बने। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि “अनुबंध प्रबंधन” सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है। यह प्रशिक्षण व्यावहारिक समस्याओं और सरकारी अनुबंधों से जुड़ी दैनिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण के प्रमुख वक्ताओं में न्यायमूर्ति विनीत कोठारी, पूर्व काश्मीरहक मुख्य न्यायाधीश, जूरात उच्च न्यायालय शामिल रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की विधियों से अवगत कराया। एडवोकेट तरुण जैन, प्रो. सिलोहू राव, डॉ. बिपिन कुमार, डॉ. आनन्द कुमार सिंह और डॉ. आर. के. पुरोहित ने भी अपने विषय-विशेषज्ञ अनुभवों से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कुलसचिव डॉ. सुनीता पंकज ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस तरह के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित होते रहेंगे। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता में सभी के सहयोग के लिए आभार भी प्रकट किया।

जैव विविधता दिवस पर कार्यशाला हुई

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आज विक्रम सिंह भाटी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र पाली में रालसा द्वारा जारी एक्शन प्लान अनुसार जैव विविधता दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें भाटी द्वारा बताया कि वृक्षा रोपण, पर्यावरण संरक्षण व लोगों में जैविक विविधता की जागरूकता लाना हमारा कर्तव्य है। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का स्रोत है। मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे पारिस्थिति तंत्र अस्तबुलित हो रहे हैं। कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न परिस्थितियों एवं जानवरों की समृद्धता एवं संरक्षण पर ध्यान दिए गए, पर्यावरण को बचाने एवं जैव विधिक सेवा से पुष्‍खी पर प्राकृतिक सन्तुलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही विभिन्न तालुका विधिक सेवा समितियों के स्तर पर भी जैव विविधता दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सचिव भाटी के मार्गदर्शन में मांगीलाल तंवर द्वारा ऑनलाइन गुगलार्थ में जैव विविधता के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उक्त दिवस के महत्व को समझाते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम, नि:शुल्क विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर स्कैम, नालसा पोर्टल, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 1५100, पॉश एक्ट, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस दौरान डॉ. अनील कुमार शुक्ला अध्यक्ष काजरी पाली, डॉ. संजय दसोरा टी.ओ., डॉ. विजय मीणा वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. एसआर मीणा वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. कीर्तिका, डॉ. कमला चौधरी आदि उपस्थित रहे।

वृद्धजनों की बताए कानूनी अधिकार

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी द्वारा सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, पाली की विजिट कर वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सचिव भाटी ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से पृथक-पृथक रूप से बातलाप कर भोजन-पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। विजिट के दौरान रसोई की सफाई, कमरों की सफाई, स्नानघर एवं शौचालयों की साफ-सफाई व्यवस्था उत्तम पाई गई। रात्रि मेहता सदस्य वृद्धाश्रम सेवा समिति ने वृद्धाश्रम के भवन एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सचिव भाटी को विस्तार से जानकारी दी गई। वृद्धाश्रम में वर्तमान में 5३ वरिष्ठ नागरिक आवासित हैं, जिनके रहने के लिए पृथक-पृथक कक्ष, बेड, पुस्तकालय इत्यादि की व्यवस्था है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम में फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ मरीजों की विषय-विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध करवाया जाता है तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच करवायी जाती है। वृद्धजनों में वृद्धजनों को नितिलिप्त पीठिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। सचिव भाटी द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता, नालसा एवं रालसा द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान वृद्धाश्रम के सदस्य राजेंद्र मेहता, कांतिलाल आदि उपस्थित रहे।

पांच लाख की धोखाधड़ी, मामला दर्ज

जोधपुर, (कासं)। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से बॉंबे मोटर चौराहा के पास में शतरंज इंस्टीट्यूटयूट खोलने एवं पार्टनरशिप के नाम पर पांच लाख रूपए ले लिए गए। नो इंस्टीट्यूटयूट खला गया और ना ही रकम वापिस लौटाई। पीडित ने नामजद व्यक्ति के खिलाफ प्रतापनगर सदर थान में धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी है। प्रतापनगर सदर पुलिस ने बताया कि मूलतः कबनूर महाराष्ट्र हाल मालवीय नगर जयपुर के रहने वाले कोस्तुम कुष्णांत गोते ने रिपोर्ट दी है। उसने रिपोर्ट में बताया कि मात वर्ष अंको मुलाकात बोम्बे मोटर के समीप दिल्ली के बुरादी निवासी मयंक शर्मा से हुई थी। यहाँ एक कार्यालय में उनके बीच में बॉंबे मोटर के पास में शतरंज इंस्टीट्यूटयूट खोलने की बात हुई थी, जिसमें पार्टनरशिप के तौर पर उसने मयंक शर्मा ने पांच लाख रूपए ले लिए। इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर वह टालमटोल बना देता रहा।

पाली में सड़क हादसे में वृद्ध की मौत

पाली, (नि.सं.)। पाली में सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार वृद्ध को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार हादसा बुधवार देर शाम को पाली के सदर थाना परिया के रूपावास गांव के पास हुआ। अज्ञात वाहन चालक ने रूपावास गांव निवासी स्कूटी सवार रूपावास गांव निवासी 75 साल के मंगलाराम पुत्र मूलाराम को टक्कर मार दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बॉक्सिंग प्रतियोगिता 25 को

पाली, (नि.सं.)। पाली जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला स्तरीय जूनियर बालक/बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता 25 मई को बोंगड स्ट्रेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में होगी। प्रतियोगिता में पाली जिले के वर्ष 2009 एवं 2010 में जन्मे बालक एवं बालिका मुक्केबाज भाग ले सकते हैं।

‘ग्रीष्म ऋतु में लू-ताप व हीट वेव से बचाव करें’

जालोर, (कासं)। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु में लू-ताप गर्मी, अत्यमान बढ़ने, ताप की लहर, हीट वेव एवं अन्य विपरीत जलवायु परिवर्तन से आमजन के बचाव एवं राहत के लिए "क्या करें व क्या ना करें" के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा ने बताया कि आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा गर्मी व ताप की लहर को देखते हुए "क्या करें व क्या ना करें" के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है। स्थानीय मौसम संबंधित खबरों के लिए टीवी देखें व रेडियो सुने तथा समाचार पत्र पढ़े या संबंधित मोबाइल एप डाउनलोड करें। पर्याप्त पानी पीयें तथा अपने आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस (ओरल रिहाइडेशन सॉल्यूसन), घर के बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) निंबू का पानी व छाछ आदि का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़े पहनें। यदि कही बाहर हैं तो अपना सिर ढके, कपड़े, टोपी

आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो : कुमावत

एक्सपायर पैंकिंग ज्यूस व सड़े फल नष्ट कराए

पाली,(नि.सं.)। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पाली शहर के बांगड अस्पताल के सामने मानसरोवर ज्युस सेंटर पर छापा डाला इस कार्यवाही के दौरान टीम को फंगस व सड़े गले फलों से भरा डी फ्रिज मिला, जहां पर जाले पर पड़ताल में रियल ज्यूस, ज्यूस बनाने में काम में लिये जाने वाले क्रश सहित अनेक खाद्य सामग्री बहुतायत मात्रा में अवधिपार मिली जिसे जब्त कर नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव व सुरेश चन्द्र शर्मा ने मय टीम कार्यवाही को अंजाम देते हुये भारतीय खाद्य मानक अधिनियम के तहत नमूनीकरण कर सेम्पलो को जांच हेतु लिया गया। साथ ही ज्यूस संचालक की जागरूकता लाना हमारा कर्तव्य है।हये हिदायत दी गयी की भविष्य में अनियमितताएं पाये जाने पर उनके फुड लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर कार अभियान के तहत मिलावट खोरों पर शिंकजा कसने को लेकर विभाग ने अपनी कम्पर कस ली है। इसके बावजूद भी मिलावटखोर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वर्ष 2025 के आकडों के अनुसार अभी कम मिलावट के रोकथाम को लेकर 142 सेम्पल लिये।

जालोर में साइबर पुलिस ने ठगी की राशि दिलवाई

जालोर, (कासं) साईबर लोकेशन भेजी और पुलिस थाना जालोर ने परिव्वादी मोतीराम के साथ हुई ठगी की सम्पूर्ण राशि 78 हजार रुपये रिफण्ड करवाई गई। मिलितरी आर्मी से पाउडर सामान जालोर से हैदराबाद ले जाने के नाम पर परिव्वादी के साथ साईबर ठगी हुई थी । परिव्वादीद्वारा साईबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने पर साईबर काईम पुलिस थाना जालोर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण राशि होल्ड करवाकर परिव्वादी के खाते में पुनः रिफण्ड करवाई गई इस वर्ष अब तक कुल 34 लाख 74 हजारो 216 रुपये की राशि पीडितों को रिफण्ड करवायी जा चुकी है।

परिव्वादी मोतीराम ने 28 मार्च 2025 को परिव्वादी श्री मोतीराम पुत्र वालाराम पट्ट निवासी गोसाई नगर धने की ढाणी पुलिस थाना सिम्रधरी बाडमेर हाल चौसरी ट्रांसफोर्ट नगर थर्ड फेस जालोर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया जिसमें अपने आप को कथित रोनक फेट केयर ट्रांसफोर्ट कंपनी का मालिक जुसुफ खान होना बताते हुए कॉल किया कि आपको मिवालिदरी आर्मी से पाउडर का सामान जालोर से हैदराबाद ले जाना है। वहां पर आपको हमारी बतायी लोकेशन पर धिवकुमार नगर व्यक्ति मिलेगा। फिर

के लिए इसे सफेद रंग या चूने से रंग दे या गोबर से लीप दें। लेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉमर्स का प्रयोग करें। अत्यधिक गर्मी के दौरान पानी की छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाएं, पशुओं को हरी घास, प्रोटीन-वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें तथा कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें। नियमित दीवारों की बजाया कैबिटी तकनीक का उपयोग करें। घर को ठंडा रखने के लिए चौड़ी दीवारें बनावाएं, अधिकतम वायु प्रवाह कर गर्मी को अवशुद्ध करने के लिए जालीदार दीवारें और लोब वाले उद्घाटनों का निर्माण करें। दीवारों को रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे चूने या मिट्टी का उपयोग करें। यदि संभव हो तो कांच के हस्तेमाल से बचें तथा निर्माण करने से पूर्व बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह लें। बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला ना छोड़ें, पंखें व नम कपड़ों का प्रयोग करें, ठंडे पानी में स्नान करें, भूमण्डलीय ऊष्मीकरण और गर्मी

को कम करने में मदद के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का उपयोग करें, पेड़ लगाएं व सूखे पत्तियों, कृषि अवशेषों व कचरे को न जलाएं, जल स्रोतों का संरक्षण करें व वर्षों के जल को संचयित करें, ऊर्जा कुशल उपकरणों, स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें, चक्कर आने व अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त डॉक्टर के पास जाये। घूप में बाहर जाने से बचे (खासकर दोपहर 12 और 3 बजे के बीच), दोपहर में बाहर भारी कार्मों से बचे, नंगे पांव बाहर न जायें, दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचें, खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाए रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें, शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए शराब, चाय, कॉफी व कॉर्बोनेटेड शीतल पेय से बचें, अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें व बासा भोजन ना करें।

पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें, ऐसे बल्लों का उपयोग करने से बचे जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं।



कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर कार्यालय में जनसुनवाई की।

पाली, (नि.सं.)। गुरूवार को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आज गुरूवार को जिले के सुमेरपुर में उनके कार्यालय में जनसुनवाई की और आमजन की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इस अवसर पर समस्याओं में उन्होंने पानी बिजली सड़क एवं अन्य की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारी से जानकारी लेकर समाधान के लिये कहा।

सुमेरपुर ,तखतगढ, शहर समेत ठागामो क्षेत्र से बड़ी संख्या में सुनवाई में पहुंचा।इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ

को सह शिक्षा के रुप में परिवर्तित करने और पुस्तकें व फर्नीचर के संबंध में सहमति प्रदान करने पर मौजूद ने आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर पार्षद देवाराम चौधरी, समाजसेवी कमलेश रावल, मदनलाल बोहरा, छगनलाल बोहरा भारूदा, शंकर काकू सांडेवार, पंडित सुरेश गौड़, समेत मौजूद रहे।

महिला ने जूते बरसाए, लोगों ने बीच-बचाव किया

पाली, (नि.सं.)। पाली कलेक्ट्रेट में गुरूवार दोपहर को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक-दुजे पर जूते बरसाए और बाल खींच कर लड़ते रहे। बाद में उन्हें दूसरे लोगों ने छुड़ावाया। शांति भंग में गिरफ्तारी के बाद इन्हें जमानत के लिए यहां लगा गया था। जमानत मिलने से पहले ही दोनों पक्ष के लोगों में फिर से तनातनी हो गई।

एक महिला के लाल पकड़कर उसे खींचा तो दूसरी महिला ने जूता उतार बरसाने लगी। हंगामा होते देख लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें शांत किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जमानत के रूपयों को लेकर इनमें फिर से तनातनी हुई। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा दोनों पक्ष मस्ताना बाबा क्षेत्र में रहते हैं। जो बुधवार शाम को झगड़ गए थे। जिन्हें जमानत के लिए एसडीएम ऑफिस लाया गया था। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में उलझ गए।

कृषक की मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती मथानिया के भैसेर कोतवाली क्षेत्र में खेत पर काम करते समय एक कृषक के मुंह में कीटनाशक चला गया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया।अस्पताल में उपचार के बीच उसकी मौत हो गई।

अभियान के तहत लक्ष्यनुरूप वृक्षारोपण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा हरियालो राजस्थान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जनकहभागिता आवश्यक है, इस हेतु आवश्यक जन जागरूकता अभियान चलाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत सहित कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी आदि मौजूद रहे।

सेना के सम्मान में रेवदर में तिरंगा यात्रा निकाली

रेवदर, (नि.सं)। रेवदर ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में आज रेवदर कस्बे में तिरंगा यात्रा संभागा प्रभारी नारायण पुरोहत, पूर्व विधायक जगसीराम के निर्देशन एवं मंडल अध्यक्ष हरीश के नेतृत्व में निकाली गई।

तिरंगा यात्रा में सैकड़ों वरिष्ठ भाजपा नेता, विविध संगठन के कार्यकर्ता और माताये बहने और स्थानीय नागरिक हाथों में तिरंगा लीये एवं भारत माता की जयघोष करते हुये बडी संख्या में शामिल हुए,

मंडल महामंत्री दशरथ सोनी ने बताया कि 6 मई को भारतीय सेना के अदम्य परा म ने पाकिस्तान को घुटनो के बल ला दिया जिससे पुरे देश में हर्ष का माहौल छा गया है और देश का हर नागरिक सेना के साहस को सलाम कर रहा है इसी क7ी में रेवदर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमे सबसे पहले भारत माता की तस्वीर को माल्यापर्ण कर व पुष्प अर्पित कर एवं पूर्व सैनिक अर्जुनदास का माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया,

तिरंगा यात्रा का प्रेसी माता से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गो से होते हुये रामजी कुटिया समापन किया गया, तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुये संभागा प्रभारी नारायण पुरोहित ने कहा कि यह यात्रा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सेना के शौर्य और परा म को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि मात्र तीन दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपनी

गिव-अप अभियान के लिए अब तक 2८0 नोटिस

जालोर, (कासं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए 31 मई तक ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जालोर जिले में अब तक 280 आपत्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झ्रवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4929 परिवारों एवं 16679 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 31 मई, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे। उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली जा जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह अधिनियम सख्त ढंड और जुर्माने का प्रावधान करता है।

योजना से नाम हटाने के लिए 31 मई तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 31 मई, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे। उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली जा जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह अधिनियम सख्त ढंड और जुर्माने का प्रावधान करता है।

जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झ्रवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4929 परिवारों एवं 16679 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट से आवेदन किए। विभागीय निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/ कर्मकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/ अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास कार या हथियार वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त हो), जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक

को निर्धारित सीमा से अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश के लिए निर्मित पक्का मकान हो, नगर परिषद क्षेत्र में 1च्छ हजार वर्ग फीट व नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है।

योजना से नाम हटाने के लिए 31 मई तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 31 मई, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे। उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली जा जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह अधिनियम सख्त ढंड और जुर्माने का प्रावधान करता है।

भारत विकास परिषद् के संस्कार शिविर का समापन

पाली , (नि.सं.)। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित विकासा स्कूल में संस्कार शिविर का समापन समारोह का आयोजन किया गया इस समारोह के मुख्य अतिथि डीडी शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री थे।

इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष नारायण रूप राय एवं प्रांतीय संपर्क संयोजक मितल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बालिकाओं द्वारा अतिथियों का बधावा गाकर स्वागत किया गया एवं वंदे मातरम गीत के पश्चात भारत विकास परिषद पाली शाखा अध्यक्ष नूतन वाला कपिल ने संस्कार शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा देश हमें दे है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे समवेत स्वर में गाया। बालिका खुशाली द्वारा शिविर के अपने अनुभव साझा किए गए उसने कहा शिविर में उसने ऐसी बातें सीखी जो उसने कभी जीवन में सुनी भी नहीं थी। प्रांतीय संयोजक संपर्क श्री मितल द्वारा बालिकाओं के शिविर की प्रशंसा की गई और कहा कि शिविर में सीखी गई बातों को जीवन में उतरो। उषा लखोटिया जीके मार्गदर्शन में बालिकाओं ने गीता के श्लोक का गायन किया जिसे सुनकर अतिथि भी अर्चनित हुए। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष नारायण रूप राय ने कहा की प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी अतः शिष्यों को शिक्षा के साथ संस्कारों में शािक्षा दी जाती थी आज की शिक्षा में बौद्धिक ज्ञान इतना अधिक दिया जाता है की संस्कार देने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है भारत विकास परिषद द्वारा आज की पीढ़ी को बाल संस्कार शिविर के माध्यम से संस्कारित करने का प्रयास सराहनीय है उन्होंने परिषद की मातृ शक्ति को साधुवाद दिया जिन्होंने अपना समय बालिकाओं को संस्कारित करने के लिए दिया। इस अवसर पर लोकमता अहल्याबाई होलकर के चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता

रोजगार सहायता शिविर आज

जालोर, (कासं)।रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर 23 मई को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक जिला मुख्यालय पर रमदा कॉलेजी परिसर, सामतीपुरा रोड में लगेगा। जिला रोजगार अधिकारी राजीव कुमार सुथार ने जानकारी दी।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने देशनोक में 1 0 3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशनोक रेलवे परिसर में शहीदों के सम्मान में लगी प्रदर्शनी गैलरी का भी अवलोकन किया।

बच्चों द्वारा बनाई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता के जयघोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री

अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1300 से

अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के आठ रेलवे स्टेशन देशनोक, गोणामेड़ी, बूंदी, माण्डलगढ़, गोविंदगढ़, मण्डावर-महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए व आरती उतारी तथा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। श्रीकरणी मंदिर निजी प्रत्यास के अध्यक्ष बादल सिंह देपावत ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह व मां करणी का साहित्य भेंट किया।

सात प्रतिनिधिमंडल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इसी दौरान, नई दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक अन्य राज्यों में बदलते समीकरणों को लेकर कयास लगा रहे हैं। बिहार, जहाँ वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में तुरंत कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं दिखता, लेकिन स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया ब्लाॅक दोनों के पक्ष और विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हो रही है, जब मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल, भले ही महत्वपूर्ण हो, घरेलू राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास हो सकती है, खासकर वह भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुट राष्ट्रीय मोर्चा बिना सकती है।

भौतीरी विवादों और राजनीतिक उठापटक के बावजूद, यह वैश्विक मिशन रणनीतिक सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद में संलिप्तता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रमाणित करने में कितना सफल होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को अगले कुछ महीनों के लिए प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि सीट ब्लाॅकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर

पार आतंकवाद में संलिप्तता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रमाणित करने में कितना सफल होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को अगले कुछ महीनों के लिए प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

नीट पीजी सीट ब्लाॅक करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि काउन्सिलिंग से पहले सभी मैडिकल कॉलेजों को फीस बतानी होगी।

करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी, शासन में समन्वय की कमी और नीतियों के ढाले पालन जैसी समस्याएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें - सभी यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग से पहले फीस का खुलासा

राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा व्यंग्य

नयी दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमाग टंडा' तथा 'खून गरम' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी को खोखले भाषण देना बंद कर यह बातना चाहिए कि देश के हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इधर-उधर की बातें नहीं करनी

■ राहुल गाँधी ने कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आपका खून कैमरों के सामने ही क्यों गरम होता है।

चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे खालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अफमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

सीट पर अपग्रेड का विकल्प मिलेगा, लेकिन नए छात्रों के लिए काउंसिलिंग नहीं खोली जाएगी। श्री स्कॉर, उत्तर कुंजी और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को सार्वजनिक

सीट ब्लाॅक करने वाले छात्रों और कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी—जैसे सिक्योरिटी डिफॉाज की जल्दी, भविष्य की नीट पीजी परीक्षाओं से अयोग्यता, और कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसिलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट ब्लाॅकिंग को रोका जा सके। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर ईडी की रेड पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की

■ तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ईडी को एक हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में राज्य विपणन निगम के खिलाफ मनी लॉण्डरिंग जांच की अनुमति दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

पीट ने केन्द्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइफ़्ट विलेज कार्यक्रम—2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर

■ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बनीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।

प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सीमात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला— केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार

इन चारों जातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

सभा को सम्बोधित करते हुए, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस दौरान 34 हजार किलोमीटर लंबी रेल पटरियाँ बनी हैं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। 47 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में छोटे और मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले देश में एक साथ 1062 रेलवे स्टेशनों के विकास की नींव रखी थी। आज इनमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 100 स्टेशन की 8 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे।

पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।

सतपाल मलिक के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारा गत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी आई ने उनके आवारा पर रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, “उन्हें (सी बी आई को) 4-5 कुर्तों-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बैठा हूं, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।” केन्द्रीय एजेंसी ने ‘चिनबाव

वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी बी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के भित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, “उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रह हो जाने के बाद, सी बी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए एये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अनंततागत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।”

वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान

बहस चली इस “स्टे” की माँग पर

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ विवादस्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उठ प्रावधानों को लेकर दी गई है, जिनमें “उपयोग द्वारा वक्फ (वक्फ बाई यूजर) सम्पत्ति, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के “विवादित” वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

■ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह आदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस बहस में भाग लिया है।

■ रिट दायर करने वाले की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने दलील दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने से मुसलमानों के साथ “डिस्क्रिमिनेशन” होगा।

माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवंई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जनित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेंद्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी को कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह और अन्य ने बहस में हिस्सा लिया। उनका तर्क था कि संशोधित कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उनके मूलभूत धार्मिक कार्यों और परम्पराओं को निशाना बनाता है, और विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना ही, वक्फ संपत्तियों को मनमाने तरीकों से जब्त

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि “उपयोग द्वारा वक्फ” (वक्फ बाई यूजर) की अवधारणा को समाप्त करने से वे ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान और धार्मिक सम्पत्तियाँ प्रभावित होंगी, जिनके औपचारिक नवीकरण नहीं हैं, लेकिन जो सदियों से धार्मिक रूप से उपयोग में हैं और अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी का विरोध किया। उनका कहना था कि इस तरह की नियुक्तियाँ मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हैं और यह अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक पंथों को अपनी संस्थाओं के संचालन में स्वायत्तता प्रदान करते हैं।

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

विवाह के तीन माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कोठारमन दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2017 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के

कुछ दिनों बाद से ही अभियुक्त ने मोटर साइकिल, सोने की चैन और दो लाख रुपये की मांग कर किरण के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं, किरण के भाई मुकेश कुमार ने भी अपने बयानों में अदालत को जानकारी दी कि किरण के आत्महत्या करने से करीब बीस दिन पहले उसकी उसके के साथ फोन पर बात हुई थी। इस दौरान किरण ने उसे बताया था कि उसका पति और ससुराल के अन्य लोग दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं।

इसके चलते 22 सितंबर को किरण ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर किरण के परिजनों ने 25 सितंबर को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक—राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भारा हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैर रोड आयाड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत चौकी, चुरी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी 1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 खूब कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908